Board of Central Excise and Customs, which collects a huge amount of money, almost three-fourths of the Central Government's revenue, which runs into Rs.1,04,000 or Rs.1,06,000 crores, that is, customs duty and central excise, is questioned and if he is arrested by the investigating agencies, it is not merely a question of failure of an individual; it is not merely a question of an individual's misdemeanour. It raises a question that something is seriously wrong in our system and it requires correction. Planning is not like the job of an accountant--plus and minus, debit and credit. It is much more than that, how to utilise the resources and how to mop up the resources. When you are going to finalise or prepare the Approach Paper for the Tenth Plan, for God's sake, please draw lessons from the experience of the Ninth Plan and the Eighth Plan; spell out your policies clearly; clearly say this is your objective and this is what you want to achieve, and, thereafter, you see whether you are trying to reach your objective and what stands in the way. In that process, I have no doubt, you will overcome the crisis. What is needed, to my mind, is that you have to bring back the confidence of the people in the system, "Yes, we can deliver the goods. If, today, our fiscal deficit has gone high; if, today, our revenue realisation has gone down; if, today, our GDP growth has gone down, surely, we can improve the situation because there is inherent strength and resilience in the system". Please create that confidence about the resilience in the system, about the effectiveness of the system. To my mind, all the other things will follow. Thank you, Madam Deputy Chairperson, for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Finance Minister, you have to lay on the Table the Supplementary Demands for Grants (General) 2001-2002.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2001-2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam Deputy Chairperson, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the First Batch of the Supplementary Demands for Grants (General) 2001-2002. [Placed in Library. *See* No. L.T. 3986/01]

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Has it been passed in the other House or not?

SHRI YASHWANT SINHA: No. It has to be laid in both Houses first.

3.00 P.M.

SHORT DURATION DISCUSSION

Economic slowdown, fall in GDP rate and deteriorating financial condition of the country in the context of mid-term appraisal of Ninth Five Year Plan - *(contd).*

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक गंभीर आर्थिक विषय पर, विशेष रूप से नियोजन के विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी। प्रणबदा ने जो कुछ कहा, उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे कि टैक्स नैट बढ़ा सकें, फिस्कल डेफिसिट घटा सकें और नए आर्थिक सुधार कर सकें, तो उसमें हमारे विपक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में विपक्ष से सहयोग मिलेगा? प्रणब मुखर्जी साहब को सब से बड़ी शिकायत यह है कि बहुत दिनों बाद आर्थिक समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं पर बजट पर चर्चा के समय चर्चा होनी चाहिए थी। तब बजट पर चर्चा को किसने रोका था? बजट पर चर्चा ठीक से इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार ही नहीं था। मैं उन पुरानी बातों पर जाना नहीं चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन समस्याओं की ओर चितरंजन जी ने ध्यान आकर्षित किया है और प्रणब जी आपने भी ध्यान आकर्षित किया है, वे समस्यायें महत्वपूर्ण हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और न हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक बात प्रणब जी आप ध्यान में रखिए और हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि भारत कोई एक टापू में नहीं रह रहा है, सारे विश्व की जो स्थिति है, जो वैश्विक स्थिति है हमें उसके अंतर्गत ही रहना है, उसमें ही सांस लेनी है और उसमें ही विकास करना है। यह एक ऐसी आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर है जिससे भारत पृथक कैसे रहेगा और इसकी चर्चा आपने क्यों नहीं की? प्रणब जी, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री नरेन्द्र मोहन : निश्चित रूप से, मैं आदरणीय उपसभापति जी की अनुमति और उनके माध्यम से ही आपको बताना चाहता हूं। यह 4 अगस्त का "इकोनोमिस्ट" है, उसमें दुनिया के और देशों की जीडीपी ग्रोथ की चर्चा है। मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 1.6 परसेंट है, जो कि जे.पी. मोर्गन ने आंकी है और इसकी चर्चा इसमें की है। अमरीका की स्थिति यह है कि वहां का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष 17 प्रतिशत गिर गया है। मैक्सिको, सिंगापुर में आउटराइट रिसैशन है। यही नहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की स्थिति क्या है? क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिस गति से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं अगर यही स्थिति रहती है तो क्या उसका प्रभाव भारत की अर्थ व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? यह एक विश्व मान्य सिद्धांत है। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव विश्व की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। वैश्विक आर्थिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों का बढ़ना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो चिंता है, वह हमारी भी चिंता है, लेकिन पचास वर्षों में जो बीज बोया है वही फसल तो हम काटेंगे। वह फसल हम कैसे काट लेंगे जो कि आप चाहते हैं कि